भाषण दिया था, उसके क्रियान्वयन के लिए माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं। मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) **The Appropriation (No. 4) Bill, 2022**

(II) **The Appropriation (No.5), Bill, 2022**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No. 4) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 2022.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (No. 5) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 14th December, 2022.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

GOVERNMENT BILLS - *Contd.*

The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022- *Contd.*

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, शायद मैं लास्ट स्पीकर हूँ, मुझे लीस्ट स्पीकर मत बना दीजिएगा। टाइम की पाबंदी ज्यादा मत बरतिएगा। ...(**व्यवधान**)... जी, बिल्कुल।

सर, 2019 में न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का एक्ट बना था और जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के तीन हिस्से होते हैं - डिबेट, डेलिब्रेट एंड डिसाइड, उसमें यह सारी बात हुई थी और उसे पूरी चर्चा के बाद पास किया गया था। वर्ष 2014, जब से माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी आए हैं, तब से एक फोर्थ डायमेंशन शुरू हुआ है, जिसमें जो अपोजिशन वॉइसेज़ हैं, जो वैल-मीनिंग ओपिनियंस हैं, उन्हें डिसमिस करने की एक प्रथा बन चुकी है। वर्ष 2019 में इस बिल को लेकर अपोज़िशन से जो-जो प्रॉब्लम्स आई थीं, अगर वे एड्रेस कर ली होतीं, तो शायद हमें 2022 में आकर यह पूरी चर्चा फिर से नहीं करनी पड़ रही होती। इसे पहले लोक सभा में अनुमति दी गई, अब यह फिर राज्य सभा में आया है, तो कहीं-न-कहीं यह एक चीज़ जरूर दर्शाता है कि हमारा जो पूरा ऐक्ट है, जिसे हम बनाते हैं, वह पूरा प्रोसेस-ड्रिवन है, rather than being efficiency-driven acts. That is why within three years we are having an Amendment here. यह जो सरकार की आदत शुरू हुई है कि नाम बदलो, काम हो जाएगा, instead we have to move towards काम करो, नाम अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर यह अंतर बहुत स्पष्ट दिख रहा है। इंटरनेशल आर्बिट्रेशन सेंटर के लिए चार-पाँच इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं - ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, टाइम-ड्रिवन और डिपेंडेबिलिटी। अगर इन चार-पाँच पहलुओं को देख लिया जाए, तो शायद कहीं-न-कहीं, we would have met with success much sooner than having to struggle to find a space and make a space in this entire system. अगर यहाँ पर सरकार ही सारी अपॉइंटमेंट्स के निर्णय लेगी, जहाँ पर आपके चेयरमैन हों, आपके सेक्रेटरी हों, आपके सीईओ हों, अगर सारे डिसीज़न सरकार से ही आने हैं, तो how would it inspire confidence in the minds of the people who are coming here to look forward to arbitration and redressal in commercial disputes? That is something that should have been looked at even in 2019; it should be addressed even now, as Shri Vivek Tankha said. He is a very experienced person and उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि टाइम-बाउंड मैनर में कितनी डिफिकल्टी होती है, जहाँ पर 33 से ज्यादा बार उनकी सिटिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो अवॉर्ड मिलना चाहिए था, वह अभी भी नहीं मिला है।

सर, हम जिस इंडिपेंडेंट एजेन्सी की बात करते हैं, उस इंडिपेंडेंट एजेन्सी पर जो सरकार का बढ़ता हुआ इंटरफेरेंस है, उसके चलते इतनी सारी तादाद में इंडियन टैक्स पेइंग सिटिजंस इंडियन सिटिज़नशिप गिव अप कर रहे हैं और इस साल तो पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर जनता में भी विश्वास टूट रहा है, तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में we are talking about a global environment, वह विश्वास कैसे बनेगा, इसकी रूपरेखा भी तैयार होना जरूरी है। Like I said earlier, the litigation continues forever. It has to be time-bound. हमें इंटरनेशनल सीट बनानी है, इसके लिए हम बाकी देशों की बात कर रहे हैं। Why is Singapore a success story? Why is London a success story? That is because, उन्होंने जो ईकोसिस्टम बनाया है, it matches the expectations of the people.

Sir, I would take one more minute. आप उसमें ऑनलाइन हियरिंग का प्रावधान करें, आप आर्बिट्रेशन बेंचेज़ बनाएं, आप स्पेशलिस्ट आर्बिट्रेशन बार बनाएं और आब्रिट्रेटर्स को अक्रेडिटेशन दें। अगर अक्रेडिटेशन मिलेगा, So, probably there would be an increased sense of confidence. I think the cost-effectiveness of it matters the most. Last, but not the least -- and I would end with this point -- Mumbai is the commercial capital of India. Most of the corporate companies look at Mumbai as the first base to set up their businesses. I am very surprised that Mumbai has not been given the due importance as was given in the previous Act that was passed, by calling it the 'New Delhi International Arbitration Centre'. We would want and hope that Mumbai's arbitration centre would get as much support as we are talking about 'GIFT cities', and we are talking about New Delhi!

With these words, Sir, I conclude what I wanted to say. Thank you.

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय महोदय, हमारी सरकार जो "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022" लेकर आई है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक के जरिये देश में संस्थानिक मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है और इस विधेयक के माध्यम से मध्यस्थता केन्द्र का नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र से बदल कर भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र किया गया है।

5.00 P.M.

माननीय महोदय, इस विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है और विधेयक के माध्यम से नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र स्थापित करने का उपबंध किया गया है। इसके तहत देश में संस्थानिक मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है।

माननीय महोदय, देश भर में आज लगभग कई मध्यस्थता संस्थान स्थापित हैं और ये सभी किसी न किसी शहर के नाम पर हैं। दिल्ली का भी अपना 'दिल्ली माध्यस्थम केंद्र' स्थापित है, लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के मध्यस्थता केंद्र की बात करते हैं, तब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे यह संस्थान "शहर या नगर केंद्रित" संस्था है और इसलिए 'नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र' के नाम को बदलकर अब 'भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र' करने की जरूरत पड़ी है, ताकि राष्ट्रीय महत्ता की संस्था होने के चलते इसकी विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो और यह अपने वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

माननीय महोदय, इस मध्यस्थता केंद्र का प्रमुख मकसद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मध्यस्थता और सुलह कराना होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुलह और मध्यस्थता के लिए ट्रेनिंग कराना और स्किल्स मुहैया कराना भी इसका मकसद होगा। इसका एक और उद्देश्य मध्यस्थता और सुलह के क्षेत्र में सुधार लाना और इस केंद्र को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित करना भी होगा। इसके अलावा, यह ऐसे कामों के संचालन के लिए प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करेगा।

माननीय महोदय, भारत एक उभरता हुआ देश है और अब हमारा देश भी मध्यस्थता का संस्थागत केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और हमारे प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आने वाले समय में मध्यस्थता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, I stand here to support the Bill. The hon. Minister has applied the policy of 'Better late than never.' It is well understood. At the same time, I would like to request the hon. Minister to use the same policy of 'Better late than never' to name Madras High Court as Tamil Nadu High Court. Only four States in this country have the names which the British have given. It is the right of the people of Tamil Nadu. We expect the Central Government to change the name of Madras High Court as Tamil Nadu High Court at the earliest.

Coming to the subject, it is certainly a step in the right direction to promote ease of doing business among the corporates. At the same time, it is just not at the corporate level that arbitration is required in the country. With the number of cases which are pending in this country, there is a need to think above the corporate level. Justice delayed is justice denied. There should be a thought where we can have arbitration at the lower level so that pending cases are dealt with at all levels. We have *Lok Adalats* and other institutions, but they do not have power to do arbitration at the lower level. That is why there is so much pendency in district courts and High Courts. So, the Government should consider opening up the arbitration route for the ordinary corporate sector also.

To conclude, as the Law Minister is present here, I would like to take this opportunity to once again draw his attention towards the need for setting up regional and Zonal Benches of the Supreme Court in each zone to mitigate the hardships of the litigants who have to travel all the way for litigation. Suitable place in Tamil Nadu can be Madurai, Trichy, Coimbatore and likewise. Thank you, Sir.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं, तब उन्होंने कानून का राज स्थापित करके दिखाया। उस वक्त तमाम गुंडे-मवाली, भू-माफिया और बलात्कारियों को प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा, जो प्रदेश छोड़कर नहीं भागे उन डेढ़ लाख लोगों को जेल में डाला गया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please,*...(Interruptions)...*

श्री रामजी : मान्यवर, मैं आपके सामने यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यहां कानून मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो कानून की बात करना ज़रूरी है। आज माननीय कानून मंत्री जी को पूरे देश में कानून का राज और कानून का खौफ़ कायम करना पड़ेगा। यहां माननीय सदस्य मज़ाक बना रहे हैं। यहां कई सदस्य बैठे हुए हैं, माननीय बृजलाल जी भी बैठे हुए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please address the Chair. *...(Interruptions)...*

श्री रामजी : बृजलाल जी डीजी थे, वे सब कुछ जानते हैं। मैं एक घटना को क्वोट करता हूं कि आज भी गरीबों से न्याय कितनी दूर है। महोदय, 14 अप्रैल, 2022 को दो बहनों के साथ बलात्कार हुआ था, यह हरदोई की घटना है। तीन पुलिस वालों ने बलात्कार किया ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please,*...(Interruptions)...* Hon. Member, it is not connected with the Arbitration Bill. *...(Interruptions)...* You are all hon. Members. *...(Interruptions)...*

श्री रामजी: मैं प्वाइंट पर आ रहा हूं। मान्यवर, चार महीने तक एफआईआर नहीं हुई।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please,*...(Interruptions)...* माननीय सदस्यगण, बैठ जाइए।

श्री रामजी : मान्यवर, चार महीने तक एफआईआर नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri Ramji, this is not right.

श्री रामजी : मान्यवर, साढ़े आठ लाख रुपये खर्च हुए। माननीय कोर्ट के द्वारा एफआईआर हुई। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। आप टॉपिक पर बोलिए।

श्री रामजी : मान्यवर, मेरी बात सुनिए, मैं गरीबों की आवाज़ बनकर आता हूं। मैं यहां पूरे देश के सामने बात रखने आया हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, settle down. ***...(Interruptions)...***

श्री रामजी : मान्यवर, एफआईआर कराने में साढ़े आठ लाख रुपये खर्च हुए और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, ...(**व्यवधान**)... दो लोगों की गिरफ्तारी हुई।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आप एक सेकंड के लिए रुकिए। मैं अनुरोध करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

डा. जॉन ब्रिटास(केरल) : यह बड़ी शर्म की बात है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय ब्रिटास जी, मैं यहां मौजूद हूं। Let us have silence. आप अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री रामजी : मान्यवर, मैं संक्षेप में रख रहा हूं, डिस्टर्बेंस होगी, तो कैसे संक्षेप में बात होगी? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप बिल के ऊपर बोलिए।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the Minister wants to hear him. ***...(Interruptions)...*** Why are they troubling? ***...(Interruptions)...***

श्री रामजी : मान्यवर, चार महीने तक एफआईआर नहीं हुई, परिवार के लोगों ने साढ़े आठ लाख रुपये खर्च किए और कोर्ट के ज़रिये एफआईआर हुई। महोदय, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि एससी/एसटी के 94 परसेंट मुकदमे लम्बित हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप बिल के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। कृपया बिल पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी : मान्यवर, माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने एक बात को क्वोट किया है। मैं उनकी बात को दोहराना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप आर्बिट्रेशन पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी : मान्यवर, देश के अंदर 4 करोड़, 70 लाख, 17 हज़ार, 398 केस लम्बित हैं और 3 करोड़, 19 लाख, 81 हज़ार, 475 क्रिमिनल केस लम्बित हैं। ...(**व्यवधान**)... अभी सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट... ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप बिल के ऊपर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी : मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में भी 71 हज़ार केसेज़ लम्बित हैं। ...(**व्यवधान**)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second, Dr. Agrawal has a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री रामजी : मान्यवर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय एनवी रमन्ना जी... ...(**व्यवधान**)...

डा. जॉन ब्रिटास : सर, यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, यह प्वाइंट ऑफ डिसऑर्डर है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One second, Dr. Agrawal, under which Rule you want to raise the point of order? ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, he has to quote the rule. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय ब्रिटास जी, ...(**व्यवधान**)... माननीय रामजी, nothing else is going on record. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Dr. Brittas, I am not listening to you. Nothing else is going on record. ...*(Interruptions)*... Dr. Brittas, I will have to name

---

*Not recorded.

you now. ...*(Interruptions)*... Yes, Agrawal*ji*, under while rule you want to raise the point of order?

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भी किसी विधेयक पर बहस होगी, तो बिल के सबस्टेंस पर होगी।...(**व्यवधान**)... मैं केवल इतना ही कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... लंबित कोर्ट का, उस बिल के सबस्टेंस का कोई मतलब नहीं है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Well taken. Thank you. माननीय रामजी, प्लीज़ आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामजी : भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय एनवी रमन्ना जी ने, माननीय प्रधान मंत्री जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में एक सम्मेलन में यह कहा था कि भारत में दस लाख लोगों पर बीस जज हैं, जो बढ़ती मुकदमेबाज़ी को संभालने के लिए नाकाफी हैं। जजेज़ के लिए 24 हज़ार पद हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में पद खाली हैं। मान्यवर, इन 24 हज़ार पदों को भरने के बाद भी एक जज के पास लगभग दो हज़ार केस आते हैं, जिनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इन जजों की पोस्ट्स में बढ़ोतरी करके भारतीय संविधान के अनुरूप इनकी भर्ती की जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं, मैं किसी के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं। डा. भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो कि एक दलित समाज से आते थे। कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब ने विश्व का सबसे सुंदर, बेहतरीन, पूर्ण जनहित, कल्याणकारी, समतामूलक संविधान देकर भारत में कई गरीबों, पिछड़ों और दलितों को मान-सम्मान देने का काम किया है। सर, हमारे कानून मंत्री जी एक आदिवासी समाज से बिलॉंग करते हैं। आज इनके ऊपर यह ज़िम्मेदारी है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इस देश में कानून मिले, उनको इंसाफ मिले, देश के अंदर कानून का राज हो और उसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के बच्चों को भी जज बनाकर वहां पर बिठाएं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत! धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Mahesh Jethmalani.

SHRI MAHESH JETHMALANI (Nominated): Sir, I will be very brief. Most of the speeches that preceded me have been a little expansive. The scope of this Bill is extremely narrow. Some suggestions have been made that international arbitration in this country is doomed to fail as people are going to prefer Singapore or United Kingdom for various reasons. It was said that the delays in this country are endemic.

Hon. Member, Sushil Kumar Modi ji has said that extravagate holidays for lawyers are to be blamed for this. Sir, these matters are the subject matter and the domain of either the Supreme Court or the Executive and they will deal with it. These

are causes for the possible failure to catch up with Singapore and London as a successful international arbitration centre. I will render to Caeser what belongs to Caeser, and, as a legislator, I will focus on the Bill in hand, which, as I said, has a very, very narrow scope.

Sir, my friend, P. Wilson, my colleague in the Bar, made a rather uncharitable statement when he said that the draftsman is to be blamed. It was said, this is such a small issue -- only a name change -- why do we have to go through all this expense and why could not the draftsman think about it in 2019? Sir, may I just say that in 2019, when this Bill was passed into a law, more than 500 Members of the Lok Sabha and more than 200 Members of Rajya Sabha examined this Bill and passed it. So, it is not only the draftsman who is to be blamed. Legislators of both the House have seen this Bill and passed it in their wisdom. So, it is a little uncharitable to blame anybody.

There is a reason why it was originally called New Delhi Centre for Arbitration and that is because it went by location. The centre to be established where hearing would take place would be New Delhi. Sir, had anybody cared to see the objects of this Bill, he or she would have come to know as to why this change was required. By the way, this is the first legislative output which concerns the area of international arbitration by the present Government. Sir, please allow me to read what the legislative object of the present amendment is. Let me read a part of it. "However, it has been felt that the Centre", located in Delhi, "being an institution of national importance, gives an impression of being city-centric, whereas it should be reflective of the aspirations to promote India as a hub of international arbitration." It says, 'India as a hub'. The words 'New Delhi' give it a kind of local flavour, but they wanted to give it international flavour. And experience post passing of the Bill-- the Bill was passed in 2019 and substantially most of the time gone in Covid -- the little time that experience brought to bear on the working of this Act showed that people were a little disrupted because of the local flavour, and it needed to be changed. My esteemed friend, hon. Member, Sukhendu Sekhar, whom I respect and have a great affection for, quoted Romeo and Juliet. But, Sir, if Juliet thought that Romeo's name was Rosemarry, she might not have expressed the same sentiments. So also, the rest of India is justifying the perturb by localizing what is a Pan-India initiative, and that is the reason for this entire Amendment.

There is only one more aspect to this Amendment. I want to be brief. It is an important aspect of the change that is brought in since after arbitration we have also brought in Mediation Bill. This Amendment probably foreshadows, for the Law Minister, sometime in the near future, I suppose, will introduce in Parliament the Mediation Bill which is even simpler than the Arbitration Act. So, the second change

that is brought about by this which people seem to have not noticed is that there is also the change in saying. Apart from arbitration, this Bill will now cover all alternate dispute resolution systems. These are the two main changes, and that is all. There is nothing dramatic about this Bill. It ought to have been unanimously passed without ado. It was a case of much ado about the thing another Member has said. And, Sir, I am optimistic that this Bill and this initiative will lead India to become the leading international center. India can become a leading international hub of arbitration. And, Sir, I am even more optimistic that under Prime Minister Modi, it will become a leading international arbitration center. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The hon. Minister, for your reply.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU): Thank you, hon. Vice-Chairman, Sir. First of all, I am extremely grateful to all the hon. Members who have given very fruitful, very important suggestions as well as raised certain questions, queries and concerns also which are plaguing the Indian system of arbitration. They have also given some way forward. I am a great learner in that sense. I always welcome all the suggestions.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

I have noted down and also applied my memory to register all the important suggestions which have come from across all sides of the House. I would like to thank Vivek Tankha ji, Sushil Kumar Modi ji, Sukhendu Sekhar Ray ji, P. Wilson ji, Sushil Kumar Gupta ji, Prashanta Nanda ji, V. Vijayasai Reddy ji, Manoj Kumar Jha ji, Bikash Ranjan Bhattacharyya ji, Binoy Viswam ji, Ram Nath Thakur ji, M. Thambidurai ji, Rakesh Sinha ji, Vandana Chavan ji, Ghanshyam Tiwari ji, Priyanka Chaturvedi ji, Sakaldeep Rajbhar ji, G.K. Vasan ji, Ramji and Mahesh Jethmalani ji for making significant contributions while taking part in the discussion.

First of all, the immediate concern which comes to our mind is why India could not emerge so far as an international hub for arbitration. यह कई लोगों ने सवाल किया है। आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। We are the fifth biggest economy in the world, yet we are not the international hub of arbitration. यह जायज़ है, हर कोई सवाल उठायेगा ही।

सर, मैंने भी कई सालों से यह सोचा है कि छोटे-छोटे देश और छोटे-छोटे शहर अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन का सेंटर बन चुके हैं, हम क्यों उभर कर नहीं आ पाये। इसके कई कारण हैं और उनमें से कुछ कारणों का ज़िक्र भी हुआ, कुछ कारण मैं भी बताऊंगा। अगर सरकार और

पूरा सदन चाहेगा, तो हम एकजुट होकर, एक आवाज से कोशिश करेंगे, तो मैं आपके सामने कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हम कदम उठा रहे हैं, उनसे आने वाले दिनों में भारत दुनिया का आर्बिट्रेशन का सेंटर जरूर बनेगा। उसी दृष्टिकोण से आज यह अमेंडमेंट लाया गया है। कोई भी नाम चेंज करने के बारे में कह सकता है, अभी नाम चेंज करने के बारे में सवाल भी उठे हैं। अगर नाम में कुछ नहीं रखा है, तो फिर हम सबका नाम है, अगर हम लोगों के नाम की कोई वैल्यु नहीं है, तो फिर किसी सेंटर की भी कोई वैल्यु नहीं है। मैं मानता हूं कि नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अगर सही नाम रखेंगे, तो अच्छे नाम से अच्छा काम भी होता है। कई सदस्यों ने इसका ज़िक्र भी किया कि भारत बहुत विशाल देश है। हम कोई सिंगापुर नहीं हैं, जहां देश ही शहर है। भारत विविधता से भरा हुआ इतना विशाल देश है, इतना बड़ा देश है, इसमें इतने शहर हैं - चेन्नई है, मुम्बई है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, दिल्ली है, श्रीनगर है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, जयपुर और अहमदाबाद है, हमारे पास इतने शहर हैं, जो वर्ल्ड क्लास शहर बनते जा रहे हैं। अपने-अपने शहर में सबका सेंटर है। आज हमारे देश में कई ऐसे सेंटर्स हैं, जो चल रहे हैं, जिनमें आर्बिट्रेशन का काम चल रहा है। सब सेंटर्स के अपने-अपने नाम हैं, उदाहरण के तौर पर बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन, मुम्बई, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मुम्बई, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई, तो मुम्बई शहर में ही इतने नाम हैं। अब कोलकाता की बात करते हैं, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोलकाता, बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोलकाता, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, कोलकाता। ऐसे कितने ही शहरों में आर्बिट्रेशन के सेंटर बने हुए हैं। दिल्ली में ही, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बना हुआ है। जब यह बिल पारित हुआ, तो सारे सदस्यों ने सोचा और उस समय सरकार ने भी सोचा कि हमारी राजधानी नई दिल्ली है और नई दिल्ली के नाम से अगर हम ड्राइव करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते-बढ़ते जब यह देखा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन ऑलरेडी दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है और एक नई दिल्ली के नाम से चलेगा, तो उसमें विरोधाभास होगा या कन्फ्यूज़न होगा या वह अच्छा भी नहीं लगेगा कि सेम नाम की दो संस्थाएं एक ही शहर में चल रही हैं।

दूसरा, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि एक विशाल देश होने के कारण पूरे भारतवर्ष को समाविष्ट करके अगर हम कहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका ज्यादातर मेम्बर्स ने समर्थन किया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। अभी तक हमारे देश में आर्बिट्रेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन जो मूल कारण है, जिसकी वजह से हम इसे इफेक्टिव नहीं कर पाये, हमारे ही देश के बड़े-बड़े बिज़नेस वाले लोग, हमारे देश के लोग विदेश को प्रेफर करते हैं, लोग सिंगापुर जाते हैं, लंदन जाते हैं, हाँगकाँग जाते हैं और अलग-अलग जगह जाते हैं। सर, इसके कई कारण हैं। मैं मानता हूं कि इस पहल के बाद हम आगे कई ऐसे चेंजेंज़ देखने वाले हैं, जिनसे हमारी उभरती हुई आर्थिक शक्ति के साथ-साथ हम एक मैग्नेट की तरह दुनिया की बिज़नेस कम्युनिटी को इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के दिन जिसको एक प्राथमिकता दी जाती है, वह सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, जहां पिछले साल 469 केसेज़ रेफर हुए हैं। हाँग काँग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में 277 केसेज़ रेफर किए गए हैं, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में 377 केसेज़ हैं। इस तरह से कई सारे केसेज़ हैं। हमारे देश के लोग भी बाहर जाते हैं, लेकिन अगर आप संख्या की

दृष्टि से देखेंगे, तो पाएंगे कि दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसकी दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से देख-रेख होती है, वहाँ पिछले साल 3,704 केसेज़ लिस्ट हुए हैं। यह बिज़नेस के वॉल्यूम के हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन हमारा देश ही इतना विशाल है कि अगर विदेश से नहीं भी आए, तो भी हमारे देश के अंदर ही संभावनाएं हैं। हम तो इंटरनेशनल सेंटर बनाना चाहते हैं, परंतु हमारे देश के लोग बाहर न जाएं, अगर हम प्राथमिकता देकर इतना भी कर सकते हैं, तो वह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना होगा।

सर, हम सबसे पहले तो अपने देश के बाहर जाने वालों को कॉंफिडेंस देना चाहते हैं कि आपको हमारी व्यवस्था के तहत यहीं पर सही आर्बिट्रेशन अवार्ड मिलेगा। उसके बाद हम उन लोगों को यहाँ पर विदेशों से आमंत्रित करेंगे। उसके लिए विश्वास कायम करना होगा।

महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने सवाल किए हैं और विवेक के. तन्खा जी ने भी इसका ज़िक्र किया कि आर्बिट्रेशन सेंटर का जो महत्व है, उसमें उसकी इंडिपेंडेंस, उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी आदि कई चीज़ें हैं। इनका हमारे ऑनरेबल मेम्बर्स ने ज़िक्र किया है। महोदय, मैं मानता हूं कि हमें सचमुच में इस क्षेत्र में बहुत सालों तक काम करना चाहिए था, लेकिन हम वह काम नहीं कर पाए।

महोदय, 2016 में माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की थी। 2016 की जो घोषणा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, 'भारत को अब अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और भारत को दुनिया के आर्बिट्रेशन का सेंटर बनना ही होगा।' महोदय, उसी सोच के साथ, उसी एलान के साथ, 2019 में नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की पहल शुरू हुई। यह कानून के रूप में लाया गया और पारित हुआ। सर, मैं इसके लिए सिंगापुर का एग्ज़ाम्पल देता हूं कि यह इतना सेंटर अट्रेक्टिव कैसे बन गया। सर, उसकी जो ज्योग्राफ़िक लोकेशन है, यह जहाँ पर स्थित है, उसके बारे में लोग सोचते हैं कि यह बहुत कन्विनिएंट है। दुनिया के किसी भी कोने से, खास करके एशियन मुल्क के अंदर सिंगापुर में पहुंचना आसान है। महोदय, दूसरा प्वाइंट वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी का है। सरकार की ओर से इतने सही इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट दिया गया है, वह इतना एफिशिएंट है कि सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और उनको तुरंत न्याय मिल जाएगा। वहाँ पर बैंक्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन्स की काफी संस्थाएं हैं और उनके हेडक्वार्टर्स भी सिंगापुर में हैं। इसकी वजह से भी उन्हें एक अट्रेक्शन मिलता है। महोदय, जो कॉमन लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग भी उसी लॉ से चलते हैं। कॉमन लॉ का हमारा जो भारतीय सिस्टम है, उसी से इंस्पिरेशन लेकर हमारी सारी व्यवस्था चल रही है। अगर हम सिंगापुर में उसी कॉमन लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से सक्सेसफुल हैं, तो यह हमारे देश में भी जरूर सक्सेसफुल हो सकता है। इसके बाद ज्यूडिशियरी के सपोर्ट की बात आती है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात का ज़िक्र किया है। मान लीजिए कि आज एक आर्बिट्रल अवार्ड दे देते हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लिमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसकी कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद वह हायर कोर्ट में जाएगा। ऐसे में कोई पार्टी सोचेगी कि अगर हम इंडिया में आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे और फैसला हो भी जाता है, पर यदि फिर से कोर्ट में चैलेंज होता है, तो कोर्ट फिर से अपना समय लेता है। ऐसे में वह सोचता है कि इंडिया जाकर तो फंसना है, इसलिए हम बाहर जाएंगे। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं आज उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता

हूं। यह संविधान की बात है कि भारतीय कोर्ट - हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर की, किसी भी फैसले की, किसी भी तरह के मीडिएशन की, आर्बिट्रेशन की, नेगोशिएशन की हियरिंग कर सकता है, उस पर पाबंदी नहीं है। मैं यहाँ यह घोषणा तो नहीं कर सकता हूं कि हम संविधान का संशोधन करके कोर्ट के अधिकार को कम करना चाहते हैं। मेरे लिए आज यहाँ पर यह घोषणा करना संभव नहीं है, लेकिन यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि अगर कोई केस किसी फोरम में तय हो जाता है और अगर किसी अदालत में फिर से ट्राई करना है, तो लोग जरूर सोचेंगे कि किस हिसाब से भारत को अपना प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाए। इसके साथ-साथ जो पेनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, सिंगापुर हो, हाँग काँग हो, लंदन हो या आप पेरिस जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, उन्होंने वहाँ पर बहुत सिस्टेमैटिक वे में अपनी व्यवस्था बनाई हुई है। हमारे देश में एड् हॉक आर्बिट्रेशन को अब तक प्रेफर किया जाता है, इसलिए जब कभी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं यह भी कहता हूं कि हमें भी इस बारे में अवेयरनैस क्रिएट करनी होगी, क्योंकि हमारी सोच और व्यवस्था ऐसी है कि हम इंडिया में एड् हॉक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड मेकेनिज़्म जो भी बनता है, उस ओर हमको जाना होगा। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की ओर जाने के लिए हम सब को पहल करनी होगी, क्योंकि अभी तक हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट एपॉइंट करते हैं तो फिर पार्टी उसी हिसाब से काम करती हैं। आर्बिट्रेशन की अपनी-अपनी चॉइस होती है, आर्बिट्रेटर्स के पास जो मामला आता है, फिर हमारे पास उतने क्वालिटी आर्बिट्रेटर्स भी नहीं हैं।

दूसरे, यहां हमारे जजों के बारे में टिप्पणी की गई। मैं इस देश का लॉ मिनिस्टर होने के नाते जजेज़ या फॉर्मर जजेज़ के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो भी रिटायर्ड जजेज़ हैं, सब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग 90 प्रतिशत तो मैं कह सकता हूं कि वे आर्बिट्रेशन प्रेफर करते हैं। अगर अब कोई असाइनमेंट देगा तो उन्हें महीने में दो लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन करेंगे तो एक हियरिंग में ही पांच लाख रुपये मिल जाते हैं तो महीने में तो करोड़ों रुपये कमाते हैं। आर्बिट्रेशन फीस की जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए आर्बिट्रेशन के लिए जो व्यवस्था है, वह बहुत एक्सपेंसिव है। न्याय के लिए किसी को खर्चा करना पड़े तो यह उचित नहीं है। इसमें गरीबों के लिए तो हम लोग न्याय देते ही हैं, लेकिन जहां बिज़नेसमेन हैं, जहां कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, यहां भी लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होगा तो हम तो ऐसी जगह जाएंगे, जहां कम एक्सपेंसिव हो और कम खर्चा लगे। मैं मानता हूं कि हमारे देश की व्यवस्था और माहौल ऐसा है कि हम बाकी दुनिया से ज्यादा सस्ते में आर्बिट्रल अवार्ड दे सकते हैं। मैं यह मानता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है, इसलिए अगर हम आज यह बिल पास करते हैं तो इस बिल में हम जो यह अमेंडमेंट लाये हैं, इसके बाद हम बाकी कार्य कर चुके हैं और हम इस तरफ काफी कदम उठा चुके हैं। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके, हम अपने काम को शुरू करना चाहते हैं।

हमारे सुखेन्दु शेखर राय जी और कई लोगों ने पूछा है कि हमने अभी तक क्या-क्या कार्य किये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, I would like to read in English the steps we have taken. In 2019, you know, how the Ordinance was brought and to make a clarification to you, it is not under the pressure of the World Bank that we have brought this Bill or the procedure. It is the Government's considered opinion and decision to bring this

Bill. If you see, since 2015, in the ranking of Ease of Doing Business, India ranked at 142 in 2015. Today, the last assessment we got in 2020 was that India's rank was 63. The rank in Enforcing Contract in 2015 was 186. How can we feel proud? We were ranked 186. Today, we have managed to bring it to 163. So, it is not under any international pressure but it is the situation, the emergent situation, which compelled the Government to take a decision. Therefore, it is a sovereign decision by the Government of India, supported by this august House. I would like to inform the hon. Member and, through you, Sir, to the hon. House. The Central Government has already appointed its officer as a custodian for the undertaking of ICADR under Section 11 of the Act *vide* Order dated 3.3.2019. Now, since the Ordinance was replaced by the Act, we have issued a Gazette Notification. When I took over as the Minister for Law and Justice, I personally ensured that this is done and the Gazette Notification was issued on 13.6.2022. The rules have been framed and notified under the aforementioned Act, and laid before the Parliament during the last Session. Last Session means the Monsoon Session. NDIAC terms and conditions, salaries, allowances, everything has been done. Form of annual statement of accounts was also submitted. Sir, NDIAC number of posts, recruitment of Registrar, Counsel and other Officers, employees' rules also have been tabled in this august House. NDIAC travelling and other allowances payable to part-time members was also tabled and also, with the approval of the Ministry of Commerce and Industry, the Director-General, FIEO, that is, Federation of Indian Export Organizations as a part-time member, that is, *ex-officio* member has been approved. The Department of Expenditure have conveyed to us that their representative will be an *ex-officio* member in the NDIAC. Now after passing of this Bill today, it will be known as the India International Arbitration Centre. We have already granted Rs. 75 lakhs to this Centre, the India International Arbitration Centre. The proposal for appointment of Chairman and two expert members, from the Ministry, we have already proposed, and it has been sent to DoPT and it will go to the ACC, that is, Appointments Committee of the Cabinet. Also, so many steps have already been taken. What I would like to mention here is that, I, personally, agree with exactly the suggestions which have come today. The Arbitration Centre must be independent. If Government has an influence in the Arbitration Centre, definitely, it will not be attractive. Then, why would people come, if they know that Government has a very serious influence in the centre? We are very mindful for that. That is why, during the proposal, I have personally conveyed it to the proposed Chairperson and the members that Government will stay at arm's length distance. We will maintain it. We will not come near you because we know the moment, the authority of the Centre is diluted by the

Government's intervention, it will lose its credibility. Today, you can't hide anything. We don't want our Centre, which is the centre of national importance to be like this. After Parliament takes a decision, the sanctity of the Centre has to be maintained. That is why, I can assure this august House that the authority, the independent credibility of the India International Arbitration Centre will not be compromised. We are very mindful of that particular matter.

Now, I would like to come to some of the basic things which most of the hon. Members have raised during the debate. My request is that I will not be able to respond to each Member because that will become very lengthy, but I would like to summarize as to what is the advantage of having an institutionalized mechanism, that means, institutionalized arbitration. It will have a pre-determined arbitration procedure, which will be laid down by the Centre only. There will be updated rules in sync with the latest developments. An efficient panel of Arbitrators and professional support will come up. There will be world-class well-built infrastructure. Also, this will help in creating and enhancing the level of the situation in 'Ease of Doing Business'. It is because we are talking about ease of living. Ease of living will come when there is a prosperity in the society, and when there is 'Ease of Doing Business' atmosphere, definitely, it will lead to the prosperity. Earlier, Sir, as regards the enforcement of contract, I am talking about the past and the present comparison, the World Bank Report states that India takes as much as 1,445 days to resolve a dispute and 31 per cent of the claim value for dispute resolution is spent during the process. These are some of the realties which we have to be very mindful. I have personally interacted with the hon. Judges of the Supreme Court, and to some extent, with the High Courts also. Without the support of the Judiciary, this effort will remain half-hearted. We are very clear. The Judiciary has also to understand as to what the Legislature has gone through and what is our objective. Our objective is very clear. I am happy to inform that the Indian Judiciary has, on many occasions, have already displayed and they have already come forward to ensure that alternative dispute resolution mechanisms in India is successful and arbitration must become robust. Otherwise, if the courts are not supportive of our cause, then our efforts will fail or they will almost be half-hearted. There are certain bottlenecks and certain problems which are in existence in our country. There is a lack of credible arbitral institution. Although we have so many arbitration centres in India of which I have the list--I am sorry, I am not criticizing them, I am not terming them--but they are not considered as credible institutions by different agencies or different bodies. There are misconceptions relating to institutional arbitration and, of course, there was a lack of Government support. Sir, legislative support was lacking, which we are fulfilling

today. That is why I am so grateful to this august House that while we are discussing this serious and important matter, we are also saying that we are united in this effort. We are definitely united. The problem is in *ad hoc* arbitration; mainly, in that, the proceedings get delayed. That is the main problem in *ad hoc* practice, which we have. Again, I am very sorry to say that the arbitrators are not treated as professionals or they are not looked upon as professionals. I am sorry to say again that the awards are not of high quality. If the arbitral awards are not of high quality, then there are negative comments from the Judiciary. Then, definitely, there is a question of credibility which comes before us. That is why the arbitral awards must stand the scrutiny of the law. If we see things rationally, we should say, "Okay, the arbitral award is of good quality." Sir, there are many more things. I do not need go at length. Of course, I have many points in hand, but I am just taking advantage of your patient hearing. Some of the hon. Members raised certain questions as to what output the Indian courts are giving, naming of the High Courts, etc. Of course, today's matter is related to arbitration and renaming of the New Delhi International Arbitration Centre, but I can assure you that in this Government, presently, under the leadership of Modi*ji*, the budgetary allocation, the proactive support to Judiciary is very well-known. No court in India can say that they are wanting the support of Government of India, especially, for infrastructure. Most of the pending cases are in the lower courts. The Supreme Court has close to 70,000 cases. On that too also I have made certain remarks in a very, very good gesture to the hon. Supreme Court that it take up those cases which are relevant and which are appropriate for the Supreme Court to take up. If the Supreme Court of India starts hearing bail applications, if the Supreme Court of India starts hearing all frivolous PILs, it will definitely cause a lot of extra burden on the hon. court itself because the Supreme Court, by and large, is treated as a constitutional court. I have personally conveyed this message to the hon. Chief Justice and other Judges of the Supreme Court that we will be with the Supreme Court, we will be with the courts of India, we will always be there to ensure that the independence of Judiciary is not tinkered with. We will always protect the independence of Judiciary and also strengthen the Judiciary. But when we talk about the pending cases which is touching five crores, definitely, the people will ask the question to the Law Minister. Many questions come in the Parliament as to why so many cases are pending. If you see, more than 4,25,00,000 cases are pending in the lower courts where the Government of India has a stake. We give money, support to create better infrastructure. But we have to also ask the Judiciary to ensure that the deserving people are given justice and unnecessary burden should also be taken care of so that they don't cause disturbances when the

court is functioning or the court is discharging its duties. The main duty of the court is to give justice; they are the arbitrators, they are the people who are going to deliver justice. But, I have always very openly stated that judgment or justice can be given on the ground also. It is not that you deliver from the court rooms alone. You can go out to the fields. Judges can also go out of the court room and deliver justice. That is the way; we are talking about the mobile courts, Lok Adalats. We are going to the field. I have personally gone to many places along with the Chief Justice of a High Court to ensure that the Lower Court Judges delivering justice on the ground. I am extremely delighted that I have seen many instances. So, people get excited, some people get emotional that without requiring to go to the courts, the courts have come to their doorsteps. That is called justice at the doorstep of the people. So, Sir, Government will do everything, but when we talk about holidays being obtained by the Judges, how much output a particular High Court or a particular Judge delivers, these are the matters definitely which concern every citizen of this country. Not only the hon. Members of this House but also every citizen of this country deserve to know as to why so many pending cases are there in our country. But, at the same time, I will ensure that from the Government of India's side, we will do everything to reduce the pendency. Now, to reduce the pendency, a series of steps have been taken, a number of initiatives have been started which I am not going to explain now because today it is not the subject. I referred this since the hon. Members have raised these queries. About the naming of Madras High Court as Tamil Nadu High Court; today hon. Member of Parliament from Lok Sabha met me and requested Bombay High Court to be named as Maharashtra High Court; Allahabad High Court to be named as Uttar Pradesh High Court; because those are the name of the cities; likewise, about Calcutta High Court also. Sir, some names of the High Courts are named after cities; there are some High Courts which are named after the States; so there are variations and I will definitely have a discussion with the hon. Chief Justice of India. Government of India is always open to discussion. And, of course, when hon. Members raised this question, it is my responsibility to ensure that the suggestions are taken and see how far and to what extent we can act. We will definitely take action to see that the sentiments of the people are reflected; the hon. Members represent the people. So, when the sentiments of the people are reflected on this august House, it is the bounden duty and obligation on the part of Government to respond positively. So, these points are well taken. Why I am not able to give any assurance is because there are certain norms. I have to go through a certain process. And, before that, if I make a statement or assurance in this august House, it may not be appropriate. Sir, there are some of the queries which I have not responded to; rest be assured that your

points are registered; my officers have taken a note of those. We will come back, if necessary. I will respond privately or separately. If necessary, I will respond in writing also. But for today, for this small, limited but important Amendment, I am extremely grateful to the hon. Members of this august House for unanimously passing this Bill. Our friends from the Left, two Members, have opposed it; in words, they have opposed it, but in spirit, they have supported it. So, I consider today's discussion as a unanimous one. I thank you very much, Sir, for giving me time. I thank the hon. House for a patient hearing.

श्री उपसभापति : धन्यवाद माननीय मंत्री जी। महज सूचना के लिए डा. जॉन ब्रिटास का एक अमेंडमेंट इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए था, परंतु उन्होंने इसे मूव नहीं किया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there are two Amendments; Amendment (No.2) by Dr. V. Sivadasan--who is not present--and Amendment (No. 3) by Shri Binoy Viswam. Are you moving it, Shri Binoy Viswam?

CLAUSE 9 - AMENDMENT OF SECTION 15

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

(No.3) That at page 2, line 27, ***after*** the words "resolution mechanism," the words "including conciliation and mediation," be ***inserted***.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 15, there is one Amendment (No. 1) by Dr. John Brittas. He is not present. The Amendment is not moved.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Special Mentions. Dr. Prashant Nanda, please.

SPECIAL MENTIONS - *Contd.*

Need for setting up a 'Craft Village' at Sukhuapada, Lalitagiri in Odisha

DR. PRASHANTA NANDA (Odisha): Lalitagiri-Sukhuapada area is famous for Stone Carving Cluster, which falls in the Buddhist Circuit. The Lalitagiri of Cuttack district and Sukhuapada of Jajpur district are adjacent to each other and is emerging as a tourist place with focus on Lalitagiri Museum set up by Archaeological Survey of India.

A detailed proposal has been submitted by Odisha State Cooperative Handicrafts Corporation Ltd. (UTKALIKA) to DC (Handicrafts), Government of India, to set up a Crafts Village at Sukhuapada and a Common Facility Centre (CFC) at Lalitagiri. DC (Handicrafts) may consider for sanction of Crafts Village proposal.

I urge the Minister of Textiles to provide financial assistance for establishment of Craft Village at Sukhuapada and Lalitagiri of Odisha. Thank you.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.